manufacturers of edible oils/vanaspati have been reduced.

(2) Permission for usage of 20 per cent expeller mustard oil in the manufacture of vanaspati has been withdrawn w.e.f. 1-8-91.

(3) RBI has frozen cash credit limits for working capital.

(4) Basket for usage of rebateable oils have been expanded by the addition of solvent extracted sesame oil and salseed fat.

(5) For augmenting the availability and acceptability of edible oils, blending of one conventional edible oil with one refined nonconventional oil (like soyabean, cottonseed and safflower) has been permitted.

(6) Government has directed all State Governments and UTs to have strict surveillance on the availability and prices of edible oils and also to undertake dehoarding operations.

(7) Edible oils have been exempted from the recent freight hike as propsoed in Railway Budget for 1991-92.

(8) Vegetable oils have been exempted from the levy of excise duties altogether.

Small scale units in consumer goods market

1510. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether the small scale industry units will be encouraged to widen its scope to meet the needs of consumer goods in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): As per Gazette Notification No. S.O. 232 (E) dated 2nd April, 1991 Govt. have *inter alia* enhanced the limit of investment in fixed assets in plant and machinery of small scale industrial undertaking from Rs. 35 lakhs to Rs. 60 lakhs and that of ancillary industrial undertaking from Rs. 45 lakhs to Rs. 75 lakhs. In the policy measures for promoting and strengthening small, tiny and village enterprises laid in Parliament on 6-8-91, a number of facilities and incentive to small scale industrial units have been mentioned. These measures are intended to encourage and widen the scope of small scale industrial units including those manufacturing consumer goods in India.

पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा आम चुनाव के दौरान भारतीय वायु सेना के वायुयानों, हेलीकॉप्टरों का प्रयोग

1511. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलि या :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल ही में सम्पन्न हुये आम चुनाव के दौरान पूर्व प्रधान मंत्री तथा उपप्रधान मंत्री द्वारा चुनाव प्रचार हेतु कितने घंटों के लिये भारतीय वायुसेना के वायुयानों और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया गया;

(ख) इन वायुयानों तथा हेलीकॉप्टरों के प्रयोग के परिणामस्वरूप भारतीय वायुसेना को कुल कितनी धनराशि दी जानी थी;

(ग) क्या यह राशि वसूल कर ली गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में हुए विलम्ब के क्या कारण है; और

(ङ) इस धनराशि की शीघ्र वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ङ)

पूर्व प्रधान मंत्री ने गैर-सरकारी दौरों के लिए 2 अप्रैल, 1991 अर्थात् राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्ग-निर्देशन के लिए जारी की गई आदर्श आचरण संहिता का पैरा 7 लागू होने की तारीख से 13 जून, 1991 अर्थात् चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तारीख तक कुल 1307.10 घंटों की उड़ान की। पूर्व उप प्रधान मंत्री को इस अवधि के दौरान गैर-सरकारी दौरों के लिए कोई वायुयान उपलब्ध नहीं कराया गया।

पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा गैर-सरकारी दौरों के लिए इस्तेमाल किए गए वायुयान के प्रभार के रूप में वायुसेना को कुल लगभग 412 लाख रुपए (चार सौ बारह लाख रु०) की अदायगी की जानी है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। वायुसेना मुख्यालय को खर्च के दावे तैयार करने से पूर्व जांच कार्य करने में कुछ समय लगता है। अप्रैल, 1991 को समाप्त अवधि के बिल तैयार कर लिए गए हैं।

1512. *[Transferred to the 10th Sep. 1991.]*

गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की मासिक आय

1513. **श्री रणजीत सिंह :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1987-88 के दौरान 237.67 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले इन लोगों की अधिकतम मासिक आय क्या है;

(ग) क्या मुद्रास्फीति की दर में हो रही वार्षिक वृद्धि को देखते हुए वर्तमान स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की मासिक आय का ऐसा आकलन सही है; और

(घ) यदि नहीं, तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को देखते हुए यह राशि कितनी होनी चाहिए?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण घरेलू खपत व्यय संबंधी हंसराज आंकड़े एकत्रित करता है। योजना आयोग इन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तथा न्यूनतम आवश्यकताओं एवं प्रभावी खपत मांग पर कैलोरी बल द्वारा संस्तुत गरीबी-रेखा के आधार पर देश में गरीबों की संख्या एवं अनुपात का अनुमान लगाता है। वर्ष 1987-88 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 237.67 मि० होने का अनुमान है।

(ख) गरीब लोगों से अभिप्राय उन लोगों से है जिनका प्रति व्यक्ति अधिकतम मासिक खपत व्यय वर्ष 1987-88 में गरीबी रेखा से नीचे अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में 131.80 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 152.13 रु० था।

(ग) और (घ) कीमत स्तर में परिवर्तनों को देखते हुए गरीबी रेखा को अद्यतन बनाया जाता है।

आम चुनावों की घोषणा के बाद सरकारी पदों पर नियुक्तियां

1514. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने आम चुनावों की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में सरकारी पदों पर नियुक्तियां की थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन आयोग ने भी ऐसी नियुक्तियां न करने के लिए कहा था;

(ग) यदि हां, तो ये नियुक्तियां कौन-कौन से विभागों में किन-किन पदों पर की गई थीं;